भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1493
दिनांक 12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में डेयरी और पशुपालन

1493 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक समर्पित सहकारी दुग्ध महासंघ बनाने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ग) मंत्रालय ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय में मराठवाड़ा क्षेत्र में पशु चारा खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए महाराष्ट्र सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
(ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)
(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)
(iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)
(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने, संगठित बाजार उपलब्ध कराने और उत्पादन के लाभकारी मूल्य के साथ डेयरी फार्मिंग से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

इसके अतिरिक्त, मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार है:

I. विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (वीएमडीडीपी): महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी उत्पादन को बढ़ाने और छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास प्रारंभ किया गया था ।

i. यह परियोजना अक्टूबर 2016 में प्रारंभ हुई थी, जिसमें पहले दिन 12 गांवों से 175 किलोग्राम दूध एकत्र किया गया था। तब से यह 3,411 गांवों तक फैल चुकी है, जिसमें 35,000 दूध उडेलने वाले शामिल हैं, और वर्तमान में औसतन 4.50 लाख किलोग्राम/दिन दूध की खरीद हो रही है। आरंभ से लेकर 20 फरवरी 2025 तक किसानों के बैंक खातों में सीधे 2303.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

ii. पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना के तहत स्वीकृत एआई परियोजना में मराठवाड़ा क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं प्रदान करने के लिए 273 कृत्रिम गर्भाधान (एआई) केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन एआई केंद्रों ने अब तक पारंपरिक वीर्य का उपयोग करके लगभग 2 लाख एआई और सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके 12,024 एआई किए हैं। इन एआई ने अब तक क्षेत्र में 20,979 आनुवंशिक रूप से उत्कृष्ट बछड़े-बछियों को जोड़ा है।

iii. दूध का लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड (एमडीएफवीपीएल) ने विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना (वीएमडीडीपी) के पहले चरण के तहत नांदेड़ सहित मराठवाड़ा के चार जिलों में दूध खरीद नेटवर्क स्थापित किया है । परिचालन क्षेत्र में नांदेड़ जिले के 247 गांव शामिल हैं तथा वर्तमान में 1673 किसान दूध की आपूर्ति कर रहे हैं। दूध संग्रह अवसंरचना में 187 दूध पूलिंग पॉइंट, 15 बल्क मिल्क कूलर तथा 1 दूध प्रशीतन केंद्र शामिल हैं।

II. महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में डेयरी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान " दुधारू पशुओं की आपूर्ति " योजना को कार्यान्वित कर रही है । केंद्र प्रायोजित योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ साझेदारी में मंत्रालय द्वारा विभिन्न पशु रोगों का टीकाकरण किया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमी विकास योजना (एनएलएम-ईडीपी) के तहत, मराठवाड़ा क्षेत्र में साइलेज निर्माण इकाइयों की 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 682.19 लाख रुपए है और अनुमोदित सब्सिडी दावा 320.47 लाख रुपए है।

राज्य योजनाओं के तहत पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा फसलों की उन्नत किस्मों के बीज 100 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर किसानों को वितरित किए गए हैं

इसके अलावा, मराठवाड़ा क्षेत्र में चारे की खेती को बढ़ावा देने के लिए, 19 मार्च 2023 को एफपीओ, अन्ना चारा उत्पादक कंपनी लिमिटेड को केंद्रीय क्षेत्र की योजना '10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन' के तहत पंजीकृत किया गया। जिसकी सीबीबीओ कृषि विज्ञान केंद्र, लातूर और कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) है। एफपीओ का प्रचालन क्षेत्र लातूर जिला है तथा यह अपने सदस्यों के साथ गोपशु चारे के व्यापार में लगी हुई है। इस चारा उत्पादक कंपनी ने अब तक 300 किसानों को अपने शेयरधारकों के रूप में नामांकित किया है, और व्यवसाय संचालन शुरू कर दिया है।

****